Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of July, 2023.

A meeting between Ambassador of United States of America to India, Mr. Eric M. Garcetti and Hon'ble Home Minister was held on 11.07.2023. During the meeting matters of mutual interest were discussed.

2. A meeting, under the Chairmanship of Hon'ble Home Minister, was held on 10th July, 2023 to review the proposed amendments in the Disaster Management Act, 2005.

3. G20 conference on "CRIME AND SECURITY IN THE AGE OF NFTs, AI AND METAVERSE" was held from 13th-14th July, 2023. Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah was the Chief Guest of the Inaugural Session and Shri Ashwini Vaishnaw, Hon'ble Minister of Railways, Communication, Electronics & Information Technology was the chief guest of the Valedictory Session and exhibition was put up at the venue with many startups and Government stalls. It was a Multi-Stakeholders Conference, comprising of Regulatory Agencies, Industries, Academic Communities and Experts. The Plenary Session which was a part of this conference was attended by G20 +9 Countries as well as invited Countries which comprised of EU and international organizations like Interpol, UNODC, Caricom, AU etc.

4. Union Home Secretary held a meeting on 19.07.2023 with the representatives of Andhra Pradesh, Odisha and Ministry of Power to discuss the issues related to development of Pumped Storage Power Projects in Andhra Pradesh & Odisha.

5. A meeting of Central Level Committee (CLC) was held on 07.07.2023 under the Chairmanship of Additional Secretary (LWE) with the Nodal Officers of Madhya Pradesh, Kerala, Odisha & Telangana under Special Central Assistance (SCA) for most LWE affected districts to review physical & financial progress.

6. 03 meetings of Project Clearance Committee (PCC) were held on 04.07.2023, 05.07.2023 & 12.07.2023 respectively under the Chairmanship of Additional Secretary (LWE) with 10 States (Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Kerala, Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra) to review progress of approved works under Special Infrastructure Scheme (SIS) for LWE effected areas.

7. Meeting of High Powered Committee (HPC) was held on 11.07.2023 and 25.07.2023 to consider the proposals pertaining to '09 States and 01 UT' Action Plans under the scheme of Assistance to States & UTs for Modernization of Police (ASUMP).

8. Review of the Ist Draft of UN Cyber Crime Convention was held on 21.07.2023 for discussing the ramifications of this convention on what could be the necessary changes in the existing systems if this convention was signed and ratified by India.

9. A meeting on targeting of Indian Co-operative Banks by Cyber Threat Groups and finding solutions was held on 31.07.2023 with Ministry of Cooperation.

10. Advisory issued to all States on 04.07.2023 to 'Know your Police: Jane 8 Peher ke Prehari' campaign under the Azadi ka Amrit Mahotsav- 'Unity' theme.

11. Ministry of Home Affairs has launched a "Scheme for Expansion and Modernization of Fire Services in the States" from the earmarked allocation of Preparedness and Capacity Building Funding Window under the National Disaster Response Fund (NDRF) for strengthening fire services in the States with a total outlay of Rs. 5,000 crore. An amount of Rs. 500 crore, out of the total outlay, has been kept for incentivizing the States on the basis of their legal and infrastructure based reforms.

12. On 21.07.2023, High Level Committee has approved proposal of Grant of additional Central Assistance to the State of Sikkim, for the Flood/Flash flood/Landslide of the year 2022 and also the proposal of revised cost estimate for setting up the Integrated Control Room for Emergency Response (ICR-ER) project in Ministry of Home Affairs (MHA). Funds to the tune of Rs. 9517.20 crore as Central share, was released to 24 States, under State Disaster Response Fund (SDRF).

13. A video conference /meeting was held under the chairmanship of Secretary (BM) on 13th July, 2023 to review the preparation of Action Plan of Vibrant Villages Programme (VVP) by the States/UTs.

14. NOC issued in respect of proposal of change in the name of

(i) "Ambewadi Railway Station" as "Dandeli Railway Station" in Karnataka "Pratapgrah" as "Maa Belha Devi Dham Pratapgarh Junction" "Antu" as "Maa Chandikadevi Dham Antu" and "Bishnathganj" as "Shanidev Dham Bishnathganj" in district-Pratapgarh, Uttar Pradesh.

(ii) Village "Tanda" as "Juni Baravali Tanda" in Udaipur, Rajasthan.

(iii) Village "Wanyachiwadi" as "Haripur" in district - Satara, Maharashtra "Kedarwadi" as "Kedargaon" in Maharashtra "Dhondgewadi" as "Revangaon Khurd", "Bhatwadi" as "Bhatwade", "Dukkarwadi" as "Rampur", "Chutiya" as "Nandgaon" in Maharashtra.

(iv) Village "Prem Kotli" as "Kotli Khurd" in district Bathinda, Punjab.

****

गृह मंत्रालय - जुलाई, 2023 में प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और कार्यक्रम

भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत, श्री एरिक एम. गार्सेटी और माननीय गृह मंत्री के बीच दिनांक 11.07.2023 को बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आपसी हित के मामलों पर चर्चा की गई।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करने के लिए 10 जुलाई, 2023 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

3. दिनांक 13-14 जुलाई, 2023 को "क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ एनएफटी, एआई एंड मेटावर्स" पर जी 20 सम्मेलन आयोजित किया गया। माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे और माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव समापन सत्र के मुख्य अतिथि थे और आयोजन स्थल पर कई स्टार्टअप और सरकारी स्टालों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। यह मल्टी-स्टेकहोल्डर्स का सम्मेलन था, जिसमें नियामक एजेंसियां, उद्योग, अकादमिक समुदाय और विशेषज्ञ शामिल थे। इस सम्मेलन के पूर्ण सत्र में जी 20 + 9 देशों के साथ-साथ आमंत्रित देशों ने भाग लिया, जिसमें यूरोपीय संघ और इंटरपोल, यूएनओडीसी, कैरीकॉम, एयू आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे।

4. केंद्रीय गृह सचिव ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पम्प्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 19.07.2023 को बैठक की।

5. वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के तहत मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा और तेलंगाना के नोडल अधिकारियों के साथ अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2023 को केंद्रीय स्तर की समिति (सीएलसी) की बैठक आयोजित की गई थी।

6. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 10 राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) के साथ अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) की अध्यक्षता में क्रमश: दिनांक 04.07.2023, 05.07.2023 और 12.07.2023 को परियोजना मंजूरी समिति (पीसीसी) की 03 बैठकें आयोजित की गई।

7. पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को सहायता (एएसयूएमपी) योजना के तहत '09 राज्यों और 01 संघ राज्य क्षेत्रों' की कार्य योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिनांक 11.07.2023 और 25.07.2023 को उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक आयोजित की गई थी।

8. संयुक्त राष्ट्र साइबर क्राइम कन्वेंशन के प्रभावों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 21.07.2023 को इसके पहले मसौदे की समीक्षा की गई थी कि यदि इस कन्वेंशन पर भारत हस्ताक्षर करता है और इसकी पुष्टि की गई तो मौजूदा प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तन क्या हो सकते हैं।

9. भारतीय सहकारी बैंकों को साइबर खतरा समूहों द्वारा लक्षित करने और इसका समाधान खोजने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ दिनांक 31.07.2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

10. आजादी का अमृत महोत्सव- 'एकता' थीम के तहत 'अपनी पुलिस को जानें: जाने 8 पहर के प्रहरी' अभियान के लिए दिनांक 04.07.2023 को सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई।

11. गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण वित्त पोषण विंडो के निर्धारित आवंटन से 5,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना" शुरू की है। कुल परिव्यय में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचे पर आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए रखी गई है।

12. दिनांक 21.07.2023 को, उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2022 की बाढ़/फ्लैश बाढ़/भूस्खलन के लिए सिक्किम राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव और गृह मंत्रालय में आपातकालीन कार्रवाई के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (आईसीआर-ईआर) परियोजना शुरू करने के लिए संशोधित लागत अनुमान के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के तहत 24 राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 9517.20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

13. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) की कार्य योजना तैयार करने की समीक्षा के लिए 13 जुलाई, 2023 को सचिव (बीएम) की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस/बैठक आयोजित की गई थी।

14. निम्नलिखित के नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया

(i) कर्नाटक में "अम्बेवाड़ी रेलवे स्टेशन" को "दांडेली रेलवे स्टेशन" जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में "प्रतापगढ़" को "मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन", "अंतू" को "मां चंडिका देवी धाम अंतू" और "बिश्नाथगंज" को "शनिदेव धाम बिश्नाथगंज"।

(ii) उदयपुर, राजस्थान में गांव "टांडा" को "जूनी बारावाली टांडा"।

(iii) जिला सतारा, महाराष्ट्र में गांव "वाण्याचीवाड़ी" को "हरिपुर" महाराष्ट्र में "केदारवाड़ी" को "केदारगांव", महाराष्ट्र में "ढोंजेवाड़ी" को "रेवनगांव खुर्द", "भटवाड़ी" को "भटवाड़े", "डुक्करवाड़ी" को "रामपुर", "चुटिया" को "नन्दगांव"।

(iv) जिला भटिंडा, पंजाब में गांव "प्रेम कोटली" को "कोटली खुर्द"।

****